‘जो शिलान्यास हमारे कार्यकाल में हो रहे हैं, उनका उद्घाटन भी हमारे कार्यकाल में हो’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चरणबद्ध व एकीकृत बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 3 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के विज़न को प्रभावी गति देने के लिए बजट 2025-26 में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। बजट में प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण और समस्त 200 विधानसभाओं का सर्वांगीण विकास निहित है, जिससे वर्ष 2030 तक प्रदेश 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकेगा।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की चरणबद्ध और एकीकृत रूप से लागू की जाने वाली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजटीय घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचना सुनिश्चित हो सके।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों का शिलान्यास हमारी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, उनका उद्घाटन भी हमारे ही कार्यकाल में हो, इसके लिए सभी घोषणाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन जनकल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के विशेष निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि सुदृढ़ आधारभूत संरचना प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के विषय पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की बजट में घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे राज्य में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई परिवहन को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश भर में हैलिपोर्ट्स विकसित कर पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए हैलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से 100 एनिकटों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित 100 विद्यालयों के क्रमोन्नयन की बजट घोषणा की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम विकसित किए जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025-26 की चरणबद्ध और एकीकृत रूप से लागू की जाने वाली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा पर्यटन को बढ़ ावा देने के लिए हवाई परिवहन को सुदृढ़ करना आवश्यक हैं। इसके लिए प्रदेश भर में हैलिपोर्ट्स विकसित कर पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए हैलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाए।

आगरा में यमुना में नहाने गईं चार बालिकाओं की मौत

आगरा, 03 जून। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मंगलवार की सुबह हुए एक बड़े हादसे में यमुना नदी में नहाने गईं छह बालिकाएं डूब गईं। इनमें से दो बालिकाओं को बचा लिया गया, जबकि चार अन्य की डूबने से मौत हो गयी।

यह हादसा थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम नगला नाथू में हुआ। मृत बालिकाओं की आयु नौ से 18 साल के बीच बताई गई है। सभी एक ही परिवार के भाइयों की संतानें थीं। मृतकों में तीन सगी और एक चचेरी बहन थी। स्थानीय गोताखोरों ने उन्हें नदी से निकाला। बचाई गई दो बालिकाओं की हालत गंभीर है, उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद न केवल एक घर, बल्कि पूरा गांव शोक और सन्नाटे की चपेट में है। बताया गया है कि थाना सिकंदरा के गांव नगला नाथू की 7-8 बालिकाएं सुबह 10 बजे के करीब यमुना नदी में नहाने पहुंच गईं।

■ एक ही परिवार की 6 से 18 वर्ष की चचेरी बहनें यमुना में नहाने गई थीं। गहरे पानी में जब बालिकायें डूबने लगीं तो पास के किसानों ने बड़े प्रयास से दो को बचाया।

रामदरबार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। जिसमें यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना आदि अनुष्ठान हो चुका है। यात्री सुविधा केंद्र में तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित हो गई है। इसके अलावा महर्षि अगस्त्य, वाल्मीकि, विश्वामित्र समेत चारों गुरु की मूर्तियों को भी स्थापित कर दिया है। देवी देवताओं की मूर्तियां जयपुर में बनी हैं। उन्हें यहां लाकर स्थापित कर दिया गया है।

अजमेर कांग्रेस ने धर्मेन्द्र राठौड़ के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया

आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष पर समानान्तर कांग्रेस गतिविधियाँ चलाने व गुटबाजी का आरोप लगाया

अजमेर, 3 जून (कासं)। अजमेर शहर कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंगलवार को विजयलक्ष्मी पार्क में आयोजित शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि कांग्रेस को तोड़ने और गुटबाजी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ की समानांतर कांग्रेस गतिविधियों और गुटबाजी के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन की अध्यक्षता एवं पीसीसी महासचिव सुनील पारवानी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में "संविधान बचाओ" अभियान को वार्ड स्तर तक पहुंचाने की रणनीति के साथ, आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मगर बैठक का मुख्य केंद्रबिंदु पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ की कथित संगठनविरोधी गतिविधियां रहीं। विजय जैन ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से अजमेर कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण राठौड़ द्वारा समानांतर कांग्रेस चलाना और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों में आने से रोकना है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों को भी विफल करने में लगे हुए हैं। जैन ने कहा अजमेर कांग्रेस का कार्यकर्ता अब पूरी तरह एकजुट है और किसी भी हालत में पार्टी को कमजोर नहीं होने देगा। जो लोग संगठन को तोड़ने और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गुटबाजी कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब समय आ गया है कि ऐसे तत्वों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जैन ने कहा कि राठौड़ अलवर जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका अजमेर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे लगातार स्थानीय संगठन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैन ने आरोप लगाया कि राठौड़ की वजह से पार्टी को हर चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों, पार्षदों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठाकर निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस के अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेन्द्र सिंह रलावता समेत, कई वरिष्ठ नेताओं ने भी खुलकर विजय जैन के रुख का समर्थन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगामी चुनावों में संगठन और मजबूत हो सके।

■ अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में अजमेर कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है तथा इसका सबसे बड़ा कारण धर्मेन्द्र राठौड़ हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बूथ पर 10 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम गठित की जाएगी, जो पार्टी की नीतियों को वार्ड स्तर तक पहुंचाएगी। बैठक के अंत में पीसीसी महासचिव सुनील पारवानी ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं एवं निंदा प्रस्ताव को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। शहर कांग्रेस की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित करने वाले प्रताप यादव, अंकुर त्यागी, श्याम प्रजापति, विपिन बैसिल, वैभव जैन, कैलाश कोमल, मंजू बलाई, सोनल मौर्य, मुजफ्फर भारती, रश्मि हिंगोरानी, देशराज मेहरा सहित, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्र.मंत्री मोदी 6 जून को कटरा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, इतिहास रचा जा रहा है, बस तीन दिन बाकी हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, शक्तिशाली चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में खड़ा है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक (यूएसबीआरएल) का हिस्सा। प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं को झेलने के लिए बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। नए भारत की ताकत और दूरदर्शिता का गौरवपूर्ण प्रतीक। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री छह जून को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल और अंजी खाद रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के विशेष कश्मीर संस्करण को हरी झंडी दिखायेंगे। इसके साथ ही वह कटरा के खेल मैदान पर सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। मोदी के दौरे के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में, विशेष रूप से रेलवे लाइनों, रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।

‘‘नरेन्दर, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं, जबकि पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने और पूरे विपक्षी गठबंधन ने इस अभियान में सरकार का पूर्ण समर्थन किया था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, लेकिन अब सवाल पूछने का समय आ गया है, पर मोदी सरकार इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं दिख रही है।

जासूसी का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़ोडा गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक शकूर खान कुछ समय पहले बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तान गया था। खुफिया एजेंसियों को उसके मोबाइल में पाकिस्तान के कई अनजान नंबर मिले हैं। इनके बारे में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है।

‘एशिया के देश अपनी जीडीपी का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदलना चाहता है।

हैगसथ की टिप्पणियों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। नेताओं ने शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर देने की सराहना की, लेकिन कई नेता अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र की आर्थिक वास्तविकताओं को पूरी तरह समझता है या उन्हें प्राथमिकता देता है।

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने सकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में देखता है। उन्होंने स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े रक्षा विस्तार पर काम कर रहा है।

हालांकि कुछ अन्य लोगों ने चिंता जताई। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अपने संबोधन में ट्रंप प्रशासन के "मनमाने" व्यापार प्रतिबंधों की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि व्यापार केवल एक सॉफ्ट पावर का उपकरण नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि की नींव है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यापार डगमगाता है, तो इसके प्रभाव किसी एक क्षेत्र से बहुत आगे तक फैलते हैं।"

अनवर के प्रमुख सलाहकार, मोहम्मद फैज़ अब्दुल्ला ने हैगसथ के 5 प्रतिशत रक्षा खर्च के लक्ष्य को "मस्तिष्क को हिला देने वाला" और "बेतुका" बताया, यह कहते हुए कि अधिकांश एशियाई देशों के लिए आर्थिक विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अमेरिका की आदर्श भूमिका अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की होनी चाहिए।" उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापार और निवेश सैन्य उपकरणों की तुलना में प्रभाव डालने के अधिक प्रभावी साधन हैं।

चीन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति से असंतोष और बढ़ गया, जो पिछले वर्षों में अमेरिकी दृष्टिकोण के खिलाफ एक वैकल्पिक आवाज़ प्रस्तुत करते थे। उनके बिना, पश्चिमी आवाज़ों को मंच मिल गया, जिनमें यूरोपीय नेता भी थे, जिन्होंने एक अलग संदेश दिया।

यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने आर्थिक परस्पर निर्भरता (इकोनॉमिक इन्टरडिपैन्डैंस) को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में रेखांकित किया, यह सुझाव देते हुए कि यूरोपियन यूनियन अधिक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार हो सकता है, जो अमेरिका के अस्थिर दृष्टिकोण की तुलना में बेहतर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉं ने समान विचार व्यक्त करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता और यूरोप तथा एशिया के बीच नये गठबंधनों की बात कही, जिससे अमेरिका और चीन के बीच एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सिंगापुर के रक्षा मंत्री चान चुन सिंग ने क्षेत्रीय मनोभाव को इस तरह व्यक्त किया: अगर हमें एक पक्ष चुनना पड़े, तो हम सिद्धांतों के पक्ष को चुनें..., जहाँ शक्तिशाली अपनी मर्जी से काम न करें और कमजोर को वो सब सहना न पड़े, जो उसे सहना पड़ता है। एशिया के अधिकांश भाग से संदेश स्पष्ट था: जब अमेरिका शांति और सुरक्षा की बात करता है, तो उसे "प्रैडिक्टबिलिटी" और "इकोनॉमिक पार्टनरशिप" भी प्रदान करनी होगी, अन्यथा, क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी आवश्यक स्थिरता के लिए कहीं और, यहाँ तक कि चीन की ओर भी, देखना पड़ सकता है।

‘आप होंगे कमल हासन पर आपको जनता की भावनाएं आहत करने का हक नहीं है’

बेंगलुरु, 03 जून। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन को उनके हालिया विवादास्पद बयान (कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है) को लेकर कड़ी फटकार लगायी और कहा कि इस टिप्पणी ने कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचायी है।

न्यायालय ने इसी के साथ हासन से पूछा कि क्या वह इतिहासकार या भाषाविद् हैं, जो ऐसा दावा कर रहे हैं।

हासन की आगामी तमिल फिल्म ‘ठग लाइफ’ के सह-निर्माता राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि अभिनेता के बयान से राज्य में वैमनस्य पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हासन की ओर से माफ़ी मांगने से मामला सुलझ जाएगा।

कोर्ट ने कहा, आप होंगे कमल हासन, पर आपको जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है। जल (पानी), नेला (भूमि), बाशे (भाषा), ये तीन चीजें नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बने हैं, इसलिए भाषा का महत्व भी आप जानते हैं। आपने इसे कमज़ोर करने के लिए कुछ कहा है।

न्यायाधीश ने हासन के बयान के आधार पर भी सवाल उठाया और कहा, क्या कोई सार्वजनिक व्यक्ति इस तरह का बयान देता है कि एक भाषा दूसरी से जन्मी है, जबकि कोई भाषा से किसी भाषा से पैदा नहीं हो सकती। इस दावे का समर्थन करने वाला मैटीरियल कहां है, आपके बयान से क्या हुआ, वैमनस्य। और कर्नाटक के लोगों ने क्या मांगा है? सिर्फ एक माफी और उन्होंने कहा है कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे? कोर्ट ने कहा "जब राजगोपालाचारी जैसी हस्ती माफी मांग सकती है तो कमल हासन क्यों नही?"

■ कन्नड़ भाषा विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को फटकारते हुए यह भी कहा कि जब राजगोपालचारी माफी मांग सकते हैं तो कमल हासन क्यों नहीं।

न्यायालय राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक में ठग लाइफ की सुचारु स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निर्देश देने की मांग की गयी थी। यह याचिका कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) द्वारा चेन्नई में एक प्रचार कार्यक्रम में हासन की टिप्पणियों के जवाब में फिल्म के बहिष्कार की घोषणा के बाद दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभिनेता की टिप्पणियों को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है और उसे संदर्भ से बाहर ले जाया गया है।

मणिपुर में बाढ़, साठ हजार लोग प्रभावित

इंफाल, 03 जून। मणिपुर में मंगलवार को हो रही लगातार भारी बारिश के कारण आयी बाढ़ से 60,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति लापता है जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगभग 11000 घर और लगभग 48 भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं वहीं 93 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन की रिपोर्टें मिली है।

उन्होंने बताया कि अरम्बाई टेंगोल, असम राइफल्स तथा सेना के जवानों ने आज हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत शिविरों की संख्या बढ़ कर 65 हो गई है तथा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भोजन एवं पानी दिया जा रहा है।

मतदान के आंकड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रक्रिया को अधिक चाक-चौबंद, मतदाताओं और हितधारकों के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर की जा रही पहलों के बीच आयोग का यह निर्णय आखिरी दो घंटों के मतदान प्रतिशत को जारी होने में विलम्ब को लेकर पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा प्राय: उठाये जाने वाले सवालों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, अभी तक पीठासीन अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्र पर हुए मतदान का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रत्याशियों के एजेंटों को बाकायदा उपलब्ध कराने के बाद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) जमा कराने की जगह पर मशीन जमा करने के बाद अंतिम आंकड़े अपडेट करते हैं। अब उन्हें मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले डाटा ईसीआईएनईटी ऐप पर अपडेट करना होगा।

आम अमेरिकी के साधारण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैश्विक रूप से सराहा जाता है और इसका उपयोग दोनों देशों के हित में किया जा सकता है।

वास्तव में, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिस्पर्धी शुल्क की घोषणा की है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं शुरू हुई हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही देशों के साथ अमेरिका गंभीर और उन्नत व्यापार वार्ता कर रहा है, और भारत उनमें से एक है। अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी इसी तरह की बातचीत कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। सामान्यत: व्यापार वार्ता में दो से तीन वर्ष लगते हैं, क्योंकि इनमें कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे होते हैं, लेकिन इन मुद्दों को अब कुछ महीनों में निपटाने की कोशिश की जा रही है।

अंदरूनी जानकारी के अनुसार, यदि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए, तो भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन से अधिक तक पहुँच सकता है। हालांकि, भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक बाजारों, विशेष रूप से भूमि और श्रम-में बड़े सुधार करने होंगे।

इन "कारक बाजारों" में सुधार करना आसान नहीं है। ये मूलत: घरेलू राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भारत की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना से जुड़े हैं। इन सुधारों के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारों तथा राजनीतिक दलों के बीच लंबी और जटिल बातचीत की आवश्यकता होगी और यही सबसे बड़ी चुनौती है।

सकारात्मक संकेत ये हैं कि कुछ राज्य इन सुधारों की आवश्यकता को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। खास बात यह है कि वे राज्य, जो इन बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं, वहाँ स्पष्ट प्रगति हो रही है, जबकि जो राज्य अपने पुराने राजनीतिक रुख में जमे हुए हैं, वे पीछे छूट रहे हैं। संभव है कि देश के भीतर प्रगतिशील और प्रतिगामी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा ही भारत के भविष्य के विकास की दिशा तय करे।

कराची में मलीर जेल से 200 कैदी भागे

कराची, 03 जून। पाकिस्तान में कराची के मलीर जिला क्षेत्र में कम तीव्रता के भूकंप के कारण जेल अधिकारियों द्वारा की गई अस्थायी आपातकालीन निकासी के दौरान 200 से अधिक कैदी जेल से भाग निकले। भ्रम और अफरातफरी के बीच बचाव कार्य बड़े पैमाने पर जेलब्रेक में बदल गया और कई कैदियों को भागने का मौका मिल गया। सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) गुलाम नबी मेमन के अनुसार, निकासी प्रक्रिया के दौरान दो हजार से अधिक कैदियों को उनकी बैरकों से गिनती के लिए लाया गया था। लेकिन सुरक्षा उपाय जल्द ही पूरी तरह से अराजकता में बदल गए, क्योंकि सैकड़ों कैदियों ने भागना शुरू कर दिया। जेल में तैनात फ्रंटियर कोर के जवानों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई फायरिंग की, लेकिन उनमें से 213 भाग निकले। दुनिया न्यूज के अनुसार, अब तक केवल 78 भागने वालों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक को फ्रंटियर कोर ने जेलब्रेक के दौरान मार गिराया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

■ सूत्रों ने बताया, इनमें से 78 पकड़े गए हैं, शेष की तलाश जारी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की "सिंदूर" पर विवादित टिप्पणी

चण्डीगढ़ , 03 जून। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घर-घर सिंदूर भेजने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथित योजना को लेकर मंगलवार को विवादित टिप्पणी की, जिसको भाजपा ने बेतुका बताते हुये कड़ी निंदा की है।

मान ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा, क्या यह वन नेशन, वन हसबैंड योजना है? उनसे भाजपा के घर-घर सिंदूर बांटने की कथित योजना को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना एक मजाक है। पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ सेना द्वारा चलाये गये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के मद्देनजर, भाजपा घर-घर सिंदूर भिजवाएगी।

दस जून को हो सकता है, महाराष्ट्र में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शरद के प्रति निष्ठा रखने लोग अजित की आलोचना करने के लिए पहले अजित से माफी माँगें। इसलिये यह विलय आसान प्रतीत नहीं हो रहा है।

इनमें से अधिकांश नेता को-ऑपरेटिव पर काबिज रहने वाले लोग हैं, जिनके पास इस समय अपने निजी चीनी मिल, निर्माण कम्पनियाँ, ठेकेदारी का व्यवसाय आदि हैं। इसलिये ये लोग अपने निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील हैं। लेकिन पवार के व्यावसायिक हित इस निर्णायक क्षण पर गठबंधन के ऊपर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि वे अपने राजनैतिक जीवन के थकान भरे अंतिम पड़ाव पर कशमकश में हैं, स्थितियाँ उनके हाथों से निकलती भी जा रही हैं तथा कुल मिलाकर, अब वे पूरी तरह रिटायर होने की स्थिति में पहुँच गये हैं। शरद पवार को अब केवल अपनी बेटी के भविष्य से मतलब रह गया है।

विशेषज्ञ ऐसा महसूस करते हैं कि सीनियर पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को इस समय मुख्य चिन्ता स्थानीय निकायों के चुनावों की है। एनसीपी के उनके क्षत्रपों के लिये ‘करो या मरो’ की स्थिति है तथा वे चाहते हैं कि कम से कम ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों तथा कुछ नगरपालिकाओं पर उनकी पकड़ बनी रहे। एनसीपी पुणे, पिम्परी चिंचवाड़ नगर निगमों के अलावा, मुख्य रुप से ग्रामीण आधार वाली पार्टी है। स्थानीय चुनाव 4 से 6 महीने में होने की उम्मीद है।

पिछले सप्ताहान्त में, शरद पवार ने बारामती में, अपने गृह क्षेत्र बारामती से जुड़े घटनाक्रम के विषय में बोलने से मना कर दिया था। प्रश्न यह था कि क्या उनका गुट मालेगाँव को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चुनाव लड़ेगा। जाहिर है, उनके समर्थक अपने गृह क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पर नियंत्रण पाने के लिये अजित पवार के पैनल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन, विलय का प्रश्न अभी प्रासंगिक बना हुआ है, जो एनसीपी के स्थापना दिवस, 10 जून तक तय हो जाना है। एनसीपी की स्थापना 10 जून, 1999 को हुई थी।

इसी बीच, पिछले सप्ताह अजित पवार उस समय बैकफुट पर आ गये थे, जब नागालैंड में उनके 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। सीनियर पवार के निकटस्थ सूत्रों ने पक्के तौर पर कहा है कि वे विलय के लिये राजी तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वे सुप्रिया और जयन्त पाटिल जैसे उनके समर्थकों के हित में अजित एवं उनके सहयोगियों के पर कतरना चाहेंगे। अजित के ओबीसी बाहुबली धनंजय मुण्डे इस समय बीड में फंसे हुये हैं तथा इसी तरह राज्य महिला निकाय की प्रमुख वैशाली चकन्कर पुणे में हुई एक दहेज मृत्यु के मामले में फंसी हुई हैं।

शरद पवार के पास इन दोनों नेताओं के विकल्प हैं। छगन भुजबल को अकेले ही मंत्रिमंडल में लिया जाना भी बहुत कुछ संकेत देने वाली घटना है। महाराष्ट्र में किसी एक, अकेले मंत्री द्वारा शपथ लिये जाने की यहपहली घटना थी। जहाँ अजित पवार भाजपा के साथ पूरी तरह सहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके चाचा की ओर से संकट आ रहे हैं।

मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में शरद पवार की प्रशंसा के पुल बाँधे हैं, जिसके निर्देश उन्हें संभवत: शीर्ष भाजपा नेतृत्व से ही मिले होंगे। वे वस्तुत: यह घोषणा करते प्रतीत हो रहे हैं कि सीनियर पवार चाहे चुनाव जीते हों या हारे हों, वे हिम्मत हारने वाले नेता कभी नहीं रहे।

अमेरिका को नहीं भा रहा, भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सैन्य उपकरण खरीदते हैं। यह अमेरिका को चिढ़ाने जैसा है। लेकिन मेरा मानना है कि अब भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है, जो काफी दूर तक जाएगा।"

लटनिक ने यह भी कहा कि भारत ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का हिस्सा है, जो डॉलर की सर्वोच्चता को चुनौती देने और अपनी खुद की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा, "ब्रिक्स, के जिसका मकसद है "आओ, डॉलर का समर्थन न करें और डॉलर वर्चस्व को खत्म करें", उसका हिस्सा होना अमेरिका को दोस्त बनाने और अमेरिकन लोगों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है।"

हालाँकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी ऐसी पहल का हिस्सा नहीं है जो अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो।

उन्होंने कहा, तो राष्ट्रपति इसे सीधे और स्पष्ट रूप से उठाते हैं, और भारतीय सरकार भी इसे सीधे और विशेष रूप से संबोधित कर रही है। और यही रास्ता है, मुद्दों को सामने रखो, उन्हें सीधे हल करो, और एक सकारात्मक स्थिति तक पहुँचो। और मुझे लगता है कि हम अब वहीं हैं।

एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी द्वारा किया गया यह खुलासा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का है, आने वाले दिनों में विपक्षी दल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

लटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की उम्मीद "बहुत जल्द" की जानी चाहिए क्योंकि दोनों देशों ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो उनके लिए काम करता है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है हमने ऐसी जगह पाई है जो दोनों देशों के लिए काम करती है। मैं इसे लेकर काफी आशावादी हूं।"

भारत में हाई टैरिफ की ओर इशारा करते हुए लटनिक ने कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसे सीधे तौर पर उठाने के इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा, "भारत शुल्कों को लेकर बहुत संरक्षणवादी है। वहाँ इस पर 100 प्रतिशत शुल्क है तो उस पर 100 प्रतिशत शुल्क है। और जब आप पूछते हैं कि क्यों, तो जवाब होता है, पता नहीं, बस ऐसा ही है।"

लटनिक ने कहा कि अब इन मुद्दों को समझदारी से देखना, उन पर विचार करना और उन्हें एक उचित स्तर तक लाना जरूरी है। उन्होंने कहा, "ताकि हम एक-दूसरे के अच्छे व्यापारिक साझेदार बन सकें। यह अब तनावपूर्ण नहीं है और दोनों पक्ष एक उचित व्यापारिक संबंध बनाने के लिए काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "तो यही सौदा है। अगर मैं कहूं कि जो चीज़ें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम उदारता दिखाएंगे, और बदले में आप अपने शुल्क कम करें, हमें बाजार तक पहुंच दें और बीच का एक सही रास्ता निकालें।"

भारत-अमेरिका संबंधों के विज़न पर बोलते हुए लटनिक ने कहा कि यह "असाधारण" बात है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका द्वारा चुने गए इकलौते व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की जनता द्वारा चुने गए हैं।

उन्होंने कहा, "अगर आप दुनिया के बारे में सोचें, तो ऐसे कितने नेता हैं जो सच में अपने देश के द्वारा चुने गए हैं? यह बहुत ही दुर्लभ है।"

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908